भाग – क

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में तीसरी बार बनी सरकार का पहला बजट है और यह मेरा सोभाग्य है कि मैं इस सदन में लगातार छठी बार वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में बजट प्रस्ताव रख रहा हूँ।

1. इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने दिल्ली के नागरिकों का विश्वास और भरोसा जीता है। दिल्ली के नागरिकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले पांच साल के 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' पर अटूट भरोसा जताते हुए जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है, उससे मेरा मन दिल्ली के अपने प्रिय बहनों और भाइयों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान से भर जाता है।

2. महोदय, यह बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब भारत सहित सारी दुनिया कोरोना – कोविड 19 की महामारी से जूझ रही है। इस महामारी की चपेट में आकर कई हजार लोग दुनियाभर में अपनी जान गवां चुके हैं। दुनियाभर के डॉक्टर मिलकर इसकी चपेट में आये लाखों लोगों को बचाने में जुटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मानव जाति को इसके प्रकोप से बचाकर रखा जा सके। मैं बजट के मूल वक्तव्य पर आने से पहले इस सदन की ओर से और सरकार की ओर से उन सभी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को सम्मान अर्पित करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको बचाये रखने में लगे हैं। मैं सरकार की ओर से सदन और पूरी दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी, उठाये जायेंगे और जितनी धन राशि की जरूरत होगी, वह उपलब्ध करायी जायेगी।

3. महोदय, दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब हमारी सरकार को चुना था तो हमने दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाने का वादा किया था। बड़े गौरव और हार्दिक प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। पिछले पांच साल के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिल्ली की पहचान विकास के मॉडल के तौर पर बनी है। आज दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण तथा आम आदमी के जीवन–स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गये सामाजिक सुरक्षा के उपायों की दिशा में एक नई पहल और नयी सोच के लिए जाना जाने लगा है।

4. महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सुयोग्य नेतृत्व वाली इस सरकार ने अपने बहुत से चुनावी वादे पूरे किये हैं और शासन–संचालन का कुशल मॉडल कायम किया है। आज इसी मॉडल को देशभर में 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के नाम से पहचान मिल रही है। और सिर्फ देशभर में ही नहीं, दुनियाभर से लोग पिछले पांच साल में इस मॉडल को देखने–समझने के लिए आ रहे हैं।

5. 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का आधार है दिल्ली के हर बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की गारंटी। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि देश में हम पहली बार शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा पर काम हुआ है। आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान हमने नहीं खुलवाये। देश में कई स्कूल और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई दशकों से हजारों बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। वो हमने नहीं शुरू करवाये। शिक्षा पर पहले भी काम हुआ है लेकिन उसमें खामी यह रह गयी कि केवल 5 प्रतिशत बच्चों को शानदार शिक्षा और 95 प्रतिशत बच्चों को बेहद कामचलाउ शिक्षा उपलब्ध करायी गयी। हमने इसी को बदला है। आज दिल्ली में हर बच्चे को, गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी वैसी ही अच्छी शिक्षा देने पर काम हो रहा है जैसी किसी सक्षम परिवार के बच्चे को मिलती है। पिछले पांच साल में 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस'

से साबित हो गया है कि सरकार अगर चाहे तो हर बच्चे को शानदार शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है।

6. 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवायें। चंद लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना और बाकि लोगों को कामचलाउ चिकित्सा व्यवस्था के रहमो–करम पर छोड देना – यह पहले होता रहा है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों तक में अच्छा इलाज हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना, 'दिल्ली के फरिश्ते' जैसी योजनाओं से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, वो चाहे अमीर हों या गरीब, सबकी जान बचाना इस सब को आज देशभर में 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के रूप में पहचान मिल रही है। और मुझे खुशी है कि देश की कई सरकारें आज इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही हैं।

7. इसी तरह दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे और देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, फ्री वाई–फाई, गली गली में स्ट्रीट लाईट और सीसीटीवी लगवाना, अनधिकृत कालोनियों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना आदि शहर को विकसित और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाये गये ऐसे कदम हैं जिनकी वजह से दिल्ली के आम नागरिक का अपनी सरकार में विश्वास बढ़ा है। राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों से लेकर गाड़ी और प्रॉपर्टी के कागज़ों की डुप्लीकेट कॉपी लेने तक में आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के जो धक्के खाने पड़ते थे, उस पीड़ा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समझा और इस तरह की 100 से अधिक सेवाओं को 'डोर स्टैप डिलीवरी योजना' के तहत लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराया। आज देश के कई राज्य आंशिक तौर पर इस योजना को भी अपने यहां लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

8. इसी तरह मेट्रो का लगातार विस्तार कर और सड़को पर नई बसें उतार कर जहां एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और मजबूत बनाया जा रहा है वहीं बसों में सीसीटीवी और बस मार्शल लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित हुआ तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करना भी 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' एक ऐसा प्रयोग है जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। आधी आबादी को परिवार और देश की इकॉनामी में भागीदार बनाने के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

9. महोदय, उपरोक्त सभी बातों का सार यह है कि आज केजरीवाल मॉडल सिर्फ गवर्नेंस का ही नहीं बल्कि इकॉनामी का भी एक उल्लेखनीय मॉडल बन चुका है। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज इस 'केजरीवाल मॉडल ऑफ इकॉनामी' की वजह से मंहगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के बावजूद दिल्ली का आम आदमी मजबूती के साथ खड़ा है। जीएसडीपी के आंकड़े, जिनका जिक्र मैं अपने वक्तव्य के अगले हिस्से में करूंगा, इसका प्रमाण है। वजह साफ है – ईमानदार सरकार के कारण आम आदमी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, व्यापारी को शोषण का सामना नहीं करना पड़ता, सरकार की नीतियों की वजह से भी दिल्ली के लाखों परिवारों के घर में हर महीने बचत हो रही है और इस सब से बचा हुआ पैसा आम आदमी स्थानीय बाजारों में खर्च कर रहा है जिससे शहर की आर्थिक प्रगति हो रही है। नोबल पुरूस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और एस्टर डुफलो ने सरकार चलाने के इसी मॉडल को 'मार्डन इकॉनामी' की संज्ञा दी है।

आर्थिक परिदृश्य

10. अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की तस्वीर सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

11. महोदय, दिल्ली के पास न तो पूर्ण राज्य का दर्जा है और न भूमि संसाधनों तक हमारी सरकार की पहुंच है। इसके बावजूद दिल्ली के मूल आर्थिक घटक बड़े मजबूत हैं। दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वर्ष 2019–20 के दौरान 10.48 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास होने की संभावना है जिससे यह पिछले साल के 7,74,870 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,56,112 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।

12. स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था के 2019–20 के दौरान 7.42 प्रतिशत की दर से विकसित होने की संभावना है जो 5 प्रतिशत की अखिल भारतीय विकास दर से काफी अधिक है। पिछले पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर का औसत 8.18 प्रतिशत रहा जो दिल्ली के अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का परिचायक है।

13. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019–20 में 3,89,143 रुपये होने का अनुमान है जो 2018–19 में 3,58,430 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 8.57 प्रतिशत अधिक है। 2015–16 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,70,261 रुपये थी और तब से इसमें 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुना अधिक है। 2019–20 में प्रति व्यक्ति आमदनी का राष्ट्रीय औसत 1,34,432 रुपये है।

14. राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली के योगदान में भी बढ़ोतरी हुई और यह 2014–15 के 3.97 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 4.20 प्रतिशत हो गया, हालांकि दिल्ली की आबादी देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.49 प्रतिशत है।

संशोधित अनुमान 2019–20

15. महोदय, वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमान के लिए 54,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जाता है जबकि बजट अनुमान में 60,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की राशि 2018–19 में खर्च की गयी 46,246 करोड़ रुपये की राशि से 18.50 प्रतिशत अधिक है। स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध खर्च को 2019–20 के बजट अनुमान में स्वीकृत 33,000 करोड़ रुपये से घटाकर 2019–20 के संशोधित अनुमान में 32,600 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। बजट अनुमान में योजना/परियोजना के तहत स्वीकृत 27,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को संशोधित बजट अनुमान 2019–20 में घटाकर 22,200 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है जो 2018–19 में हुए 15,625 रुपये के खर्च से 42 प्रतिशत अधिक है।

16. सरकार का बकाया ऋण 2015–16 के 33,304 करोड़ रुपये से घटकर 2018–19 में 32,732 करोड़ रुपये हो गया है जिससे कर संकलन में सुधार और बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्ज पर निर्भर न रहने जैसे उपायों से बेहतर वित्तीय प्रबंधन का पता चलता है। 2018–19 में हमारी सरकार का कर्ज–जीएसडीपी अनुपात 4.22 प्रतिशत था जो देश के सभी राज्यों से कम है।

पूरक अनुदान मांग 2019–20

17. महोदय, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 16.0815 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं अनुपूरक मांगों के लिए सदन से स्वीकृति का अनुरोध करता हूं।

बजट अनुमान 2020–21

18. अध्यक्ष महोदय, मैं अगले वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2020–21 के लिए कुल 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का प्रस्ताव किया जाता है जिसमें स्थापना खर्च और प्रतिबद्ध देयताएं, स्थानीय निकायों को अंतरण, भारत सरकार को चुकाया जाने वाला ब्याज और मूलधन, परिवहन तथा जल और विद्युत सब्सिडी आदि के 35,500 करोड़ रुपये और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने के लिए 29,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। 65,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में राजस्व खर्च के 48,070.47 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च के 16,929.53 करोड़ रुपये शामिल हैं।

19. 65,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 44,100 करोड़ रुपये के हमारे कर राजस्व, 800 करोड़ रुपये के गैर–कर राजस्व, 1100 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्तियों, जीएसटी के अंतर्गत 7,800 करोड़ रुपये के मुआबजे, 4,141 करोड़ रुपये के लघु बचत ऋणों, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं और अन्य प्राप्तियों से मिलने वाले 1,808 करोड़ रुपये, 626 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय करों के हिस्सों से मात्र 325 करोड़ रुपये और बकाया राशि हमारे प्रारंभिक शेष से प्राप्त होगी। 2020–21 में 65,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट 2019–20 के 54,800 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 18.50 प्रतिशत अधिक है।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

20. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2020–21 में स्थानीय निकायों को 6,828 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी जबकि 2019–20 के बजट अनुमानों में इसके लिए 6,380 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। स्थानीय निकायों को कुल वित्तीय सहायता में कर संग्रह में 2,299 करोड़ रुपये का हिस्सा, स्टाम्प और रजिस्ट्रशन शुल्क में 1,805 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी और

एकबारगी पार्किंग चार्जेज आदि शामिल है। विभिन्न विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हम 2020–21 में स्थानीय निकायों को 2,724 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करते हैं।

प्रमुख कार्यक्रम, योजनाएं और परियोजनाएं 2020–21

21. महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा रखना चाहूंगा जो अगले वित वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट का अहम हिस्सा हैं।

शिक्षा

22. महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा कि शिक्षा का कार्य 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का आधार है। दिल्ली सरकार, देश की एकमात्र सरकार है, जो पिछले पांच साल में अपने कुल बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में खर्च करती आयी है। पिछले पांच साल में हमने शिक्षा को नई उचांई तक पहुंचाया है। हमारे प्रयासों और कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि आज शिक्षा की वजह से दिल्ली की ख्याति देश–विदेश में बढ़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन और शिक्षकों एवं बच्चों की मेहनत से परीक्षा परिणाम लगातार सुधर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे अब प्राईवेट स्कूलों की तरह अच्छी स्कूल बिल्डिंगस में शानदार डेस्क पर बैठकर पढ़तें हैं। उनके लिए लैब, लाईब्रेरी और खेल की सुविधायें विकसित हुईं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जा रहे काम और स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन केवल शानदार इमारतों और अच्छे परीक्षा परिणामों पर नहीं हो सकता। अगर हमें शिक्षा के माध्यम से देश को वर्ल्ड–क्लास सीटीजनस देने हैं तो अपने स्कूलों को भी वर्ल्ड–क्लास कंपीटीशन में उतारना होगा। हमारी तैयारी है कि हम अपने स्कूलों को भी

और अच्छा करें, शिक्षकों को भी अच्छी ट्रेनिंग दें और शिक्षा व्यवस्था में भी वो सब बदलाव करें जो हमारे सभी बच्चों को वर्ल्ड–क्लास कंपीटीशन में मजबूती से खड़ा कर सकें।

23. अध्यक्ष महोदय, आज हमे भरोसा है कि हमारे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो विश्वस्तरीय है। अपने इसी दावे को पुख्ता करने के लिए हमारी सरकार 2024 में होने वाले पीसा टेस्ट में शामिल होने का निर्णय कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि 'पीसा', शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अतंरराष्ट्रीय शैक्षिक आंकलन प्रक्रिया है जो हर तीन साल के अंतराल पर होती है। यह प्रक्रिया इस बात का आंकलन करती है कि किसी देश या राज्य में 15 साल की उम्र के बच्चों ने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका स्तर अंतरराष्ट्रीय मानकों और जरूरतों पर कितना खरा उतरता है। इसमें दुनिया के लगभग 80 विकसित और अति विकाससील देश भाग लेते हैं। हमारा मानना है कि पिछले पांच साल की मेहनत को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन गवर्नेंस के जरिये हम दिल्ली को 2024 में दुनिया के शैक्षिणक मानचित्र पर स्थापित कर देंगे। अगले वित वर्ष से शिक्षा के लिए बजट प्रस्ताव और हमारी तैयारी इसी बात को ध्यान में रखकर की जा रही है।

24. पिछले पांच साल के हमारे प्रयास केवल अच्छी स्कूल बिल्डिंग बनवाने और अच्छे परीक्षा परिणाम लाने तक सीमित नहीं रहे हैं। हमने शिक्षकों की देश–विदेश में ट्रेनिंग करवायी जिससे हमारे शिक्षक दुनियाभर के प्रयोगों और अनुभवों से सीख कर अपनी कक्षाओं में निरंतर नये प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे केवल किताबी ज्ञान और अच्छी मार्कशीट तक सीमित न रह जायें। सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत भी की है जिससे बच्चों में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता का विकास तो हो ही रहा है, साथ ही परिवार में माता–पिता के साथ और अपने सहपाठियों आदि के साथ उनके संबंधों एवं व्यवहार में बेहद सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। बच्चों में स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ा है और वो भावनात्कम रूप से मजबूत हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हेप्पीनेस करिकुलम के तहत नसर्री से आठवीं क्लास तक के

करीब 8 लाख बच्चों का पहला पीरीयड हैप्पीनेस क्लास का लगाया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी निरंतरता के साथ पोजीटिव इमोशनल लर्निंग का यह शायद दुनिया में अकेला प्रयोग है। यही वजह है कि अमेरिका की फस्ट लेडी श्रीमती मिलानिया ट्रंप सहित अफगानिस्तान, बंगला देश, कनाडा, नीदरलैंड आदि देशों के शिक्षा मंत्री, मेयर इत्यादि खुद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास अटैंड कर चुके हैं। देश के भी करीब एक दर्जन राज्यों के शिक्षा मंत्री और लगभग हर राज्य के अधिकारी अथवा शिक्षक–प्रशिक्षक हैप्पीनेस क्लास अटैंड कर चुके हैं।

25. हैप्पीनेस क्लास की ही तरह सरकार ने एक और अभिनव प्रयोग उद्धमशीलता के क्षेत्र में किया है। नवीं से बाहरवीं क्लास के 7.5 लाख बच्चों के लिए रोजाना एक पीरीयड 'अन्तरप्रयोनोरशिप माईडसेट क्लास' का होता है। इसके तहत बच्चों के मन से डर निकालने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने, उनकी सोच को रचनात्मक और विश्लेषणात्मक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा मकसद है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर केवल और केवल नौकरियां ढूंढने वाले ही न बने बल्कि अपनी शिक्षा के दम पर नौकरिया पैदा करने वाले भी बने। और अगर नौकरी भी करें तो उनका माईंडसेट अन्तरप्रयोनाल हो। वो जो भी करें, निडरता के साथ और नई सोच के साथ करें। 4 साल के इस पाठयक्रम में पहले ही वर्ष में बच्चों में जबरदस्त आत्मविश्वास देखने को मिला है।

26. इसी के साथ हमारी सरकार एक नया देशभक्ति पाठयक्रम भी लेकर आ रही है। यह पाठयक्रम अनुभवी शिक्षाविदों एवं समाज के विद्वजनों की मदद से तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर बच्चा अपनी स्कूल की उम्र में ही सही मायने में देशभक्त बनकर निकले। वह एक अच्छा प्रोफशनल तो बने ही, एक अच्छा नागरिक भी बने। वह अपने देश और अपने देश के लोगों के प्रति प्यार और सम्मान से जीना सीखे।

27. अध्यक्ष महोदय, इस तरह आप देख सकते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम के जरिये हम हर बच्चे को एक सवेदनशील और अच्छा इंसान बनाने पर काम कर रहे हैं। अन्तरप्रयोनोर माईडसेट करिकुलम के जरिये उसे एक अच्छा, आत्मविश्वास से भरा प्रोफशनल बनाने पर काम कर रहे है और देशभक्ति पाठयक्रम के जरिये उसे अपने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों से प्यार और गर्व करने पर काम करेंगे।

28. स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए चुनौती, मिशन बुनियाद, प्रगति आदि अभियान चलाने और बोलचाल की अंग्रेजी की विशेष कक्षायें आदि से बच्चों में सीखने के अवसर और परीक्षा परिणामों में लगातार सुधार हुआ है। इन सब प्रयासों को अगले वित वर्ष में जारी रखा जाएगा। बच्चों में अखबार पढ़ने की रूचि विकसित करने के लिए हम अगले साल से सभी बच्चों को लगातार अखबार देने की योजना भी शुरू करेंगे। विद्यार्थियों के संवाद कौशल में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष में विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया जिनमें 40,000 विद्यार्थियों को अंग्रेजी में बोलचाल के कौशल का विकास किया गया। ग्यारहवीं कक्षा के करीब 25,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में पहले से ही शामिल किया जा चुका है। यह कार्यक्रम आगे भी चालू रहेगा। इसके लिए 12 करोड़ रूपये की राशि अलग से रखी गयी है। स्कूलों में बोलचाल की अंग्रेजी की योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अब इस कार्यक्रम का विस्तार उन विद्यार्थियों के लिए भी करने का प्रस्ताव है जो पिछले पांच वर्षों में स्कूलों से परीक्षा पास कर चुके हैं। इसके अंतर्गत उनके समग्र व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ उन्हें प्रतियोगिता की दुनिया के लिए तैयार किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसे एक लाख विद्यार्थियों के लिए 60 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव है।

29. सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और नये स्कूल बनाने का कार्य अगले वर्ष भी उसी गति से जारी रहेगा। पिछले कार्यकाल के दौरान 8,500 नये कमरे स्कूलों में नये बनवाये गये और 12,000 नये कमरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा

2020–21 में 175 करोड़ रुपये की लागत से 17 नये स्कूल भवनों का निर्माण–कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है ताकि शिक्षा तक पहुंच का दायरा बढ़े।

30. सरकार की योजना है कि अपने सभी स्कूलों के सभी क्लासरूमस को हाईटैक डिजीटल क्लासरूम बनाया जाये। अगले 5 वर्ष में 9, 10, 11 व 12 कक्षा के हरेक क्लासरूम को डिजीटल क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया जायेगा। यह कार्य इसी वर्ष से शुरू होगा और हर स्कूल में कम से कम 10 क्लासरूमस को डिजीटल क्लासरूमस में बदला जायेगा। इसके लिए प्रस्तावित बजट में 100 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों और जिला मुख्यालयों को शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है। सभी स्कूलों की सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी अंतिम चरण में है और इसे जून 2020 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

31. शिक्षा देने के लिए अध्यापकों की लगातार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग कराना पिछले 5 सालों में भी हमारी प्राथमिकताओं में रहा था। करीब 1,365 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने केम्ब्रिज, फिनलैंड और एनआईई सिंगापुर में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया। करीब 700 प्रधानाचार्यों ने आईआईएम अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग में भाग लिया। यह कार्यक्रम अगले वर्ष भी जारी रहेंगे। इसके अलावा हम अपने टीचर्स और प्राधानाचार्यों को कुछ नये देश जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि एस्टोनिया आदि भी भेजेंगे। मैंटर टीचर, शिक्षक विकास समन्वयक और क्लस्टर लीडरशिप सत्रों के जरिए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के बीच पीअर लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीखने संबंधी सामग्री को ऑनलाइन देखने के लिए सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को टैब्लेट्स दिये गये हैं।

32. अगले वर्ष से स्कूल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी और विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य संबंधी विवरण वाला बहूद्देश्यीय पहचान पत्र दिया जाएगा। इस योजना के लिए 22

करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। बच्चे के शेक्षणिक विकास में माता–पिता की भूमिका को समझते हुए पिछले 5 साल में हमने पैरंट टीचर मीटिंग को एक उत्सव के रूप में स्थापित किया। जो माता–पिता कभी अपने बच्चों के शिक्षकों से पूरी पढ़ाई के दौरान नहीं मिल पाते थे अब उन्हें साल में कम से कम तीन बार मेगा पीटीएम में बुलाया जाता है। हर शिक्षक एक–एक अभिभावक से बच्चों के बारे में व्यक्तिगत संवाद करता है। बच्चे के शैक्षणिक विकास में माता–पिता की भूमिका को अब हम अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता दोनो के लिए विशेष पैरेटिंग वर्कशॉपस आयोजित की जायेंगी। यह कार्य दिल्ली बाल अधिकार आयोग (डीसीपीसीआर) के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ डीसीपीसीआर द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून और अन्य सरकारी नीतिओं के तहत, हर बच्चे को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता और उनकी सहभागिता के बारे में अध्ययन भी कराया जायेगा ताकि दिल्ली के हर बच्चे को 'अच्छी शिक्षा की गारंटी' के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वायदे पर कार्य किया जा सके। इन कार्यों के लिए 2020–21 में डीसीपीसीआर के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया जाता है।

33. हमारी सरकार का मानना है कि शिक्षा समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाये। यह तभी संभव है जब हम शिक्षा को समाज की आज की जरूरतों और कल की संभावनाओं के साथ जोडेंगें। इसके लिए हमें अपने पाठयक्रम और परीक्षा प्रणाली में भी वो बदलाव करने होंगे ताकि हमारे छात्र किताबी ज्ञान से उठकर व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर सकें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें। इस वर्ष हमारे पास नसर्री में जो बच्चा आ रहा है वह 14 साल बाद यानि 2034 में स्कूल से बाहर निकलेगा। इन 14 वर्षों में दुनिया बहुत बदल जायेगी। अपना जीवन जीने से लेकर तकनीक तक में आमूल–चूल परिवर्तन हो चुके होंगे। ऐसे में नसर्री क्लास से ही हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमारी सरकारी लगातार इस बात पर चिंतन करती रही है और इसके लिए दो नयी पहल मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ जिन पर अगले वित वर्ष से काम शुरू होना है। पहला है –

पाठ्यक्रम में आमूल–चूल परिवर्तन करना। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है। जिसमें सरकारी और निजी, दोनों ही तरह की संस्थाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों को शामिल किया जाएगा। यह समिति देश विदेश के विभिन्न मॉडल और नये प्रयोगों का अध्ययन कर नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इसी कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है – दिल्ली के अपने राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना। नये बोर्ड का मकसद है शिक्षा और परीक्षा की ऐसी प्रणाली स्थापित करना जिसमें बच्चे रटकर नंबर लाने की जगह समझकर नंबर लाने की शिक्षा ले सकें और आगामी दुनिया की संभावित प्रतिसपर्धा के लिए खुद को तैयार कर सके। इसके लिए 62 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें एससीईआरटी का बजट भी शामिल है।

34. महोदय, दुनियाभर में अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन यानि 3 से 6 साल तक की उम्र में बच्चे के सही तरीके से विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए अध्ययनों में यह बात सामने आयी है कि जिन बच्चों को अच्छी अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन मिली यानि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच उनके शरीर और दिमाग के सोचने, समझने व काम करने की क्षमताओं पर ठीक से काम हुआ, वे बड़े होकर खुशहाल और सफल जीवन जीते हैं, उन लोगों की तुलना में जिन्हें ये अवसर नहीं मिले। हमारे देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों से लेकर प्ले स्कूल और नसर्री केजी के प्रयोग तो हुए हैं लेकिन इनमें अभी अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन के जरिये बच्चे के शारारिक मानसिक विकास पर काम नहीं हो रहा है। अर्ली चाईल्डहुड एजुकेशन को गुणवत्तापूर्णक बनाने और नियमित करने के लिए सरकार एक नया कानून लेकर आयेगी।

35. अब जबकि हमारे स्कूलों में 20,000 नये कमरे जोड़ने का काम लगभग पूरा हो रहा है और नये स्कूल बिल्डिंगस भी बन रहीं हैं। ऐसे में हम अपने बहुत सारे स्कूलों को जनरल शिफ्ट के तहत चला सकेंगे। इस साल से दो शिफ्ट में चलने वाले करीब 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में बदलने का प्रस्ताव है। जनरल शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में छुट्टी के बाद बच्चों के सर्वागीण

विकास के लिए विशेष गतिविधियां और प्रशिक्षण आयोजित होंगे। जैसे कि कौशल विकास, खेल–कूद, कला नृत्य ड्रामा इत्यादि। छुट्टी के बाद के समय में अंग्रेजी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं – स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानी आदि विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

36. सरकार ने 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विगत वर्षों में शुरू किये। इनकी लोकप्रियता और मांग को देखते हुए तय किया गया है कि अब हर जोन में लगभग 5–5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जायेंगे। इन स्कूलों में से हरेक में किसी एक विषय जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अथवा कॉमर्स एवं आर्टस अथवा खेल–कूद अथवा वोकेशनल के क्षेत्र में एक्सीलेंस पर जोर रहेगा।

37. विगत वर्षों में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुयी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डीटीयू आदि के नये कैम्पस खोलने के साथ–साथ उच्च शिक्षा के लिए 16 नये संस्थान शुरू किये गये। साथ ही कई वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी शुरू किये गये। पिछले कार्यकाल के अंतिम सत्र में इस विधान सभा से 2 नये विश्वविद्यालय बनाने का बिल पास हुआ था – दिल्ली खेल विश्वविद्यालय तथा दिल्ली स्किल एवं अतंरप्रयोनोरशिप यूनिवर्सिटी। सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी स्थापना हो और इनमें एडमीशन भी शुरू हों। खेल विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए इस बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है। दिल्ली स्किल एवं अतंरप्रयोनोरशिप यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए इस बजट में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण और आत्मप्रेरित शिक्षक तैयार करने के लिए दिल्ली टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी शुरू करने का प्रस्ताव इस बजट में है। गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर भवन का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। इस परिसर में 1500 अतिरिक्त विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सकेगा। धीरपुर और रोहिणी में भी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिसरों का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

38. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय (डीटीयू) के द्वितीय चरण, जिसकी अनुमानित लागत 292 करोड़ रुपये है, के निर्माण कार्य का अवार्ड किया जा चुका है। 320 करोड़ रुपये की संशोधित लागत की इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलाजी–द्वितीय चरण परियोजना पूरी हो चुकी है और इससे विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता वर्तमान 1200 विद्यार्थियों से बढ़कर 2500 हो जायेगी। एनएसयूटी परिसर में अतिरिक्त भवन निर्माण और नरेला में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला टेक्निकल विश्वविद्यालय के नये परिसर के निर्माण का कार्य 2020–21 में शुरू किया जाएगा। सरकार ने ओखला में जी.बी. पंत राजकीय इंजीनियरिंग कालेज और जी.बी. पंत टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट के परिसरों को एकीकृत करने की 526 करोड़ रुपये की परियोजना की दिशा में भी पहल की है। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इससे मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार होगा और इसकी क्षमता 3000 विद्यार्थियों की हो जाएगी। विभाग द्वारा आईटीआई पूसा और पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एकीकृत परिसर को खोलने की प्रक्रिया जारी है जिससे विद्यार्थियों और अध्यापकों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

39. मैं वित्त वर्ष 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 15,815 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव करता हूँ, जो कि कुछ बजट का 24.33 प्रतिशत है, जिसमें 443 करोड़ रूपये अन्य विभागों के शिक्षा संबंधी योजनाओं के शामिल है। 7031 करोड़ रूपये विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गये हैं। यह राशि संशोधित बजट अनुमान 2019–20 के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है।

स्वास्थ्य

40. महोदय, दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का दूसरा सबसे बड़ा आधार है। मोहल्ला क्लीनिक और आधुनिक सुविधाओं

वाले अस्पताल के जरिये दिल्ली के हर नागरिक को क्वालिटी हैल्थ केयर देना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में शामिल है।

41. स्वास्थ्य सेवाओं को गवर्नेस में सर्वोपरि रखे जाने का मुख्यमंत्री जी का यह विचार ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज सारी दूनिया कोरोना से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का दायित्व निभाते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई स्तरों पर पहल की और हर स्तर पर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। दुनियाभर से आने वाले भारतीयों के लिए कोरनटाइन सुविधायें युद्ध स्तर पर उपलब्ध करायी गयी। इसके लिए वर्तमान वित वर्ष के संशोधित अनुमानों में ही 3 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और मेरा सदन को आश्वासन है कि भविष्य में इसके लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करायी जायेगी।

42. हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 451 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 24 पॉलिक्लीनिक और 36 मल्टी स्पेसिएलिटी/सुपर स्पेसिएलिटी अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अप्रैल से दिसंबर 2019 तक लगभग 55 लाख नागरिकों को मोहल्ला क्लीनिकों के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, जबकि 2.25 करोड़ रोगियों का उपचार दिल्ली सरकार के अस्पतालों और पॉलिक्लीनिक के माध्यम से हुआ है। मौजूदा चिकित्सालयों को उन्नत बना कर 94 पॉलिक्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या भी बढ़ा कर 1000 की जाएगी। मैं मोहल्ला क्लीनिक और पॉलिक्लीनिक के लिए 365 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान करता हूँ।

43. सरकार ने 10,000 बिस्तरों की क्षमता बढ़ा कर 26,000 बिस्तर करने के लिए, मौजूदा अस्पतालों को उन्नत बनाने और विस्तारित करने तथा नये अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरु कर

दिया है। 16 मौजूदा अस्पतालों को उन्नत बनाने और विस्तारित करने के लिए 2578 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी जा चुकी है और कुछ अस्पतालों में निर्माण कार्य शुरु भी हो चुका है। मौजूदा अस्पतालों के विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण से 16,000 नये बिस्तर उपलब्ध होंगे। बुराड़ी और आम्बेडकर नगर में अस्पतालों का काम पूरा हो चुका है और इनमें स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी ही शुरु हो जाएंगी। द्वारका में अस्पताल का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। 2019–20 के संशोधित अनुमान 195 करोड़ की तुलना में 2020–21 में 724 करोड़ रुपये का प्रावधान नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों को उन्नत बनाने के लिए किया गया है।

44. दिल्ली में आरोग्य कोष के जरिए उपलब्ध कराई जा रही फ्री ट्रीटमेंट, सजर्री, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक स्कीम और चिकित्सा उपचार अब 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के दायरे में आएंगे। इस योजना में लगभग 1016 सर्जिकल पैकेज निःशुल्क शामिल किए गए हैं। मैं 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ, जिसमें एक सौ करोड़ रुपये का प्रावधान दिल्ली आरोग्य कोष भी सम्मिलित है।

45. स्वास्थ्य सेवाओं मे एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए 'मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना' लेकर आ रही है। इसके तहत हैल्थ आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे और दिल्ली के सभी निवासियों को वितरित किए जाएंगे। हैल्थ आईडी कार्ड को सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जायेगा। इसके लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जा चुकी है। इन योजनाओं के लिए 2020–21 के लिए 70 करोड़ रुपये रखे जाने का प्रस्ताव है।

46. सरकार ने गैर–पंजीकृत केंद्र/मशीनों के बारे में सूचना देने और स्टिंग/डिकॉय आपरेशन के लिए पीसी और पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत 'खबरी पुरस्कार योजना' को मंजूरी दी है।

इसके तहत सूचना देने वाले को 50,000 रुपये और सच को सामने लाने के लिए रोगी बनने वाले को 1,50,000 रुपये का ईनाम देने की व्यवस्था है।

47. हमारी सरकार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता तथा आम लोगों और विभिन्न पक्षों द्वारा अपेक्षित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 'दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक' नाम से व्यापक अधिनियम लाएगी।

48. गैर–रेडियोलॉजी प्रयोगशाला नैदानिक सुविधा सार्वजनिक निजी भागीदारी से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार टेली–रेडियोलॉजी सुविधाएं और मजबूत की जाएंगी। इन योजनाओं के लिए 2020–21 में 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

49. दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020–21 में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करेगी।

50. मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग ने नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ बिल्कुल बर्दाशत न करने की नीति अपनाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने दिसंबर 2019–20 तक तय नियमों का उल्लंघन करने वाली 32 निर्माण इकाइयों और 107 बिक्री परिसरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

51. मैं 2020–21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,704 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। इसमें 6,555 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 1,149 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। 3,952 करोड़ रुपये की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्कीम, कार्यक्रम और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई है, जो कि वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमान 2,551 करोड़ रुपये से 55 प्रतिशत अधिक है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

52. महोदय, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगले 5 वर्ष के अंदर दिल्ली के हर घर को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की गारंटी दी है। देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिलना ही चाहिए। यह भी 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का अहम हिस्सा है। सरकार ने गारंटी कार्ड में दिये गये आश्वासन के अनुसार इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रत्येक परिवार को 20 हजार लीटर पानी की मुफ्त आपूर्ति भी जारी रहेगी।

53. इसकी तैयारी में पूरी दिल्ली में 3,341 बल्क वाटर मीटर लगवाये जा रहे हैं। ये सभी मीटर्स जुलाई से काम करना शुरू कर देगें। इसके बाद पानी की मात्रा का हिसाब रखने, पानी की आपूर्ति युक्तिसंगत बनाने और समानता के आधार पर इसका बंटवारा करना आसान हो जायेगा।

54. पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी के तट पर 4 डीसेन्ट्रालाईजड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे जिनकी क्षमता करीब 4 एमजीडी की होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 इन्सटोलेसन में से 439 में रेन वाटर हारवेस्टिंग स्थापित करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। 155 अन्य इन्सटोलेसन में भी रेन वाटर हारवेस्टिंग इसी साल स्थापित करने का लक्ष्य है। 1605 अनधिकृत कालोनियों को पाइप लाइनों के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम के दायरे में लाया गया है। इसमें से 1,549 कालोनियों में पानी की सप्लाई शुरू हो गयी है और 56 अन्य में पानी की आपूर्ति शुरू करने के बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 40 कालोनियों में काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 22 जलाशयों को पानी से फिर से लबालब करने के कार्य का ठेका दे दिया है। इसके लिए अवजल का शोधन कर पर्याप्त गुणवत्ता वाले पानी से इन तालाबों को भरा जाएगा। जलमल शोधन क्षमता बढ़ाकर 607 एमजीडी कर दी गयी है और शोधन क्षमता का उपयोग 500 एमजीडी के स्तर पर है। इंटरसेप्टर जलमल परियोजना के पूरी तरह चालू होने से क्षमता में निंरतर बढ़ोतरी होगी।

55. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देश की पहली सरकार है जिसने हाथ से मैला साफ करने के लिए लोगों को काम पर लगाने से रोकने के कानून (पी.ई.एम.एस. एक्ट) को सही अर्थों में लागू किया। दिल्ली जल बोर्ड ने एक परियोजना शुरू की है जिसके जरिए सीवर की सफाई के लिए इंसान को मैनहोल में उतारने के अमानवीय तरीके को बंद करने पर ध्यान दिया है। इससे उन लोगों के लिए मशीन से सफाई करने के कार्य में उद्यमिता के अवसर पैदा हुए है जो परम्परा से ही साफ–सफाई से संबंधित सेवाओं में काम कर रहे थे।

56. दिल्ली जल बोर्ड सीवर लाइनों से रहित इलाकों में सीवर विस्तार के लिए मास्टर प्लान–2031 पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रहा है। 434 अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछाकर इन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है। 597 अन्य कालोनियों में यह कार्य जारी है और इसके दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

57. दिल्ली जल बोर्ड ने 'मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना' शुरू की है। यह ऐसे इलाकों के लिए है जहां सीवर लाइनें तो हैं लेकिन लोगों ने अपने घर के लिए कनेक्शन नहीं लिए हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड अपने खर्च पर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा जिसमें संस्थापना शुल्क, प्रारंभिक शुल्क, सड़क बहाली शुल्क और सीवर आवेदन पत्र की कीमत भी शामिल है।

58. यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर की अभिनव परियोजना का कार्य 98 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है और नालों के करीब 141 एमजीडी अवजल की सीवर शोधन संयंत्रों में सफाई की जा रही है।

59. मैं 2020–21 में दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर अमल के लिए 3,724 करोड़ रुपये के बजट और दिल्ली के 6 लाख लाभार्थियों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की फ्री लाइफलाइन वाटर सब्सिडी योजना के लिए 467 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा 110 करोड़ रुपये 'मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना' के लिए भी आबंटित किये गये हैं। 2020–21 में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए कुल आबंटन 2019–20 के संशोधित अनुमान से करीब 70 प्रतिशत अधिक है। इसका कारण यह है कि अनधिकृत कालोनियों, सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों और इंटरसेप्टर सीवरेज के लिए अधिक धनराशि आबंटित की गयी है।

ऊर्जा

60. महोदय, आज देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने हर महीने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जीरो बिजली बिल योजना शुरू की, भले ही उनका स्वीकृत लोड कितना ही क्यों न हो। इसके अलावा 201 से 400 यूनिट मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 800 रुपये की सब्सिंडी दी जाती है। पूरी दिल्ली के करीब 90 प्रतिशत परिवार बिजली में सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। सब्सिडी योजना से बिजली के संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है क्योंकि उपभोक्ता सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपनी खपत कम से कम करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरकार सिक्खों के खिलाफ 1984 में हुए दंगों के पीड़ितों को बिजली की खपत 400 यूनिट तक सीमित रखने पर शत–प्रतिशत सब्सिडी देती है। अदालत परिसरों के भीतर वकीलों के चैम्बर्स के लिए भी विशेष बिजली सब्सिडी योजना का विस्तार कर उन्हें भी इसका फायदा दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषक उपभोक्ताओं को खेती वाले कनेक्शनों के लिए नियत शुल्क में 105 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 20 रुपये प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती है। ये सब योजनायें

'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का अहम और बहुचर्चित हिस्सा हैं और अगले वित वर्ष में भी जारी रहेंगी। मैं विद्युत सब्सिडी 2020–21 के बजट में 2820 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव करता हूं।

61. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले लोगों/संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी इमारतों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों और न्यायालय आदि में सौर संयंत्र लगाने की कार्यवाई चल रही हैं। दिल्ली में जनवरी 2020 तक कुल 161.898 मेगावाट के लगभग 3589 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके थे। किसानों ने मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना के अंतर्गत सौर बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया है।

62. जहां तक नेटवर्क में सुधार और उसमें वृद्धि करने का सवाल है, दिल्ली की बिजली कंपनियां नेटवर्क क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि और बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑटोमेशन के लिए कार्य कर रही हैं। वितरण कंपनियां दिल्ली के विभिन्न भागों में उलझे हुए बिजली के तारों को हटाने के लिए कार्य करेंगी ताकि इनसे जान–माल के लिए कोई खतरा न हो और शहर भी सुंदर बने।

63. मैं 2020–21 के बजट अनुमान में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2977 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ, जिसमें 125 करोड़ रुपये कार्यक्रम/योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हैं।

पर्यावरण और वन

64. दिल्ली की आबो–हवा को साफ रखना और दिल्ली को हरा–भरा बनाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में शामिल है। विभिन्न प्रयासों से वायु प्रदूषण को विगत 5 वर्षों में 25 प्रतिशत कम किया गया था। अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य है इसे दो–तिहाई और कम करना है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसमें जन भागीदारी के लिए पूरी दिल्ली में सघन अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रूप्ये का प्रस्ताव करता हूं। इसके तहत घर पर ही कूड़े–कर्कट की छंटाई, सिर्फ एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने, ग्रीन रूफ अवधारणा के तहत छतों पर पेड़–पौधे लगाने, गुलदस्ता भेंट करने की बजाय पौधे को उपहार में देने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग करने, कम दूरी के स्थानों को साइकिल से जाने, पटसन और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने, कागज की बर्बादी रोकने और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से उत्सव मनाने, पर्यावरण सम्मेलनों आदि का भी आयोजन किया जाएगा। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण के कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन सिटीजन अवार्ड दिये जाएंगे।

65. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके तहत बने नियमों पर अमल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रही है लेकिन श्रमशक्ति के अभाव में इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इसलिए मैं 2020–21 में 2 करोड़ रुपये की लागत से पर्यावरण विभाग में 'एनवार्यमेंट मार्शल्स' की नयी योजना का प्रस्ताव करता हूं ताकि इस कार्य के लिए समर्पित श्रमशक्ति उपलब्ध हो जाए।

66. इसके साथ ही प्रदूषण को बड़े पैमाने पर दूर करने वाले स्मॉग टावर स्थापित करने की परियोजनाओं पर अमल की भी जरूरत है। मैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ''प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन'' योजना के तहत 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

67. हमारी सरकार ने दिल्ली में हरित पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र और वृक्षों के दायरे में बढ़ोतरी के विभिन्न उपाय किए हैं। इन पहलों के परिणाम स्वरूप वन और हरित क्षेत्र का दायरा 2015 के 299.77 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2019 में 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस प्रकार कुल क्षेत्र की तुलना में हरित क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर 21.88 हो गया है। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ पौधें लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2020–21 में 22 हरित एजेंसियों द्वारा 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

परिवहन

68. महोदय, 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गाारंटी दी है। इसके तहत सरकार ने 11,000 से अधिक बसें और 500 कि.मी. से ज्यादा लंबी मैट्रो लाईन बिछाने का लक्ष्य रखा है। करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नई बसों का जुड़ना शुरू हो गया है। सरकार की दूरदर्शी योजना के तहत आधुनिक सीसीटीवी युक्त और शायद देश में पहली बार 'डिस्ऐबल्ड फ्रैंडली लिफ्ट' वाली बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की गयी हैं। कॉमनवैल्थ खेलों के आयोजन के बाद पहली बार नई लो–फ्लोर बसें अब दिल्ली के परिवहन बेड़े में शामिल हो रही हैं। कुल मिलाकर 2,485 नयी बसें (1,300 डीटीसी और 1,185 क्लस्टर बसें जिनमें 685 बिजली से चलने वाली बसें भी शामिल हैं) वर्ष 2020–21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1,880 बसें (444 डीटीसी और 1,436 क्लस्टर बसें) 2021–22 से खरीदी जाएंगी। इस तरह 11,000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए 250 करोड़ रुपये और क्लस्टर बसों की वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 1,100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

69. अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली में जमीन की उपलब्धता न होने के कारण बसों को खरीदना और उन्हे संचालित करना एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन अब सरकार ने दूरदर्शिता अपनाते हुए औखला, हरीनगर, वंसत विहार और हसनपुर सहित चार डिपों को मल्टीलेवल बस डिपो में बदलने का फैसला किया है। ये शायद देश में अपनी तरह के पहले मल्टीलेवल डिपो होंगे।

70. महिलाओं की आर्थिक सक्षमता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अक्तूबर 2019 से उन्हें डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली करीब 6,500 बसों में महिलाऐं निःशुल्क आने–जाने में सक्षम हुई है। यह योजना अगले वर्ष भी जारी रहेगी।

71. हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, खास तौर पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की हिफाजत को लेकर बहुत चिंतित है। बसों में मार्शल तैनात किये गये हैं और सभी बसों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगायी जानी है। इतना ही नहीं, क्लस्टर योजना के अंतर्गत जो नयी बसें शामिल की जाएंगी और डीटीसी के बेड़े की बसों में सीसीटीवी कैमरे, आपात स्थिति मदद के लिए पैनिक बटन और वाहन की स्थिति का पता लगाने प्रणाली लगी रहेगी।

72. मैट्रो के तीसरे चरण में अतिरिक्त कॉरीडोर बनाने और एनसीआर में इसके 158 कि.मी. विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है। दो कि.मी. का बकाया कार्य इसी वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार ने मैट्रो चतुर्थ चरण परियोजना के सभी छह कॉरीडोरों को मंजूरी दे दी है। लेकिन भारत सरकार ने मैट्रो चतुर्थ चरण परियोजना के पैकेज में से प्राथमिकता वाले तीन कॉरीडोरों : जनकपुरी – आर.के.आश्रम, एयरोसिटी – तुगलकाबाद और मुकुंदपुर – मौजपुर को ही मंजूरी दी है। मैट्रो के चौथे चरण हेतु डी.एम.आर.सी. को 200 करोड़ रूपये 2018–19 में दिये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान 2019–20 में 1,324 करोड़ रुपये आबंटित किये गये है। मैं 2020–21 में 900 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

73. हमारी सरकार ने दिल्ली विद्युतचालित वाहन नीति को 2019 में स्वीकृति प्रदान की। इसमें पुराने वाहनों के स्थान पर विद्युतचालित वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है ताकि परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन में कमी आए जिससे दिल्ली की वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। मैं राज्य विद्युत चालित वाहन निधि के लिए 2020–21 में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

74. मैं 2020–21 में सार्वजनिक परिवहन के लिए .5941 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ। 2020–21 में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए 2678 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

सड़क परिवहन

75. महोदय, आउटर रिंग रोड में आइआइटी से एनएच–8 तक कॉरीडोर सुधार योजना के हिस्से के रूप में मुनिरका पेट्रोल पम्प से लेकर केन्द्रीय बेस पोस्ट आफिस तक तीन लेन के फ्लाई ओवर का काम पूरा हो चुका है। परियोजना का दूसरा चरण यानी इनर रिंग रोड, बेनिता जौरेज मार्ग और सान मार्तिन मार्ग के जंक्शन पर 2 लेन वाले अंडरपास का निर्माण जून 2020 में पूरा होगा।

76. पिछले बजट में की गयी घोषणा के अनुसार एनएच–10 पर रामपुरा, त्रिनगर/इंदरलोक और कर्मपुरा, दिल्ली में पुलों को चौड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 20 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और पूरी परियोजना 2020–21 में पूरी हो जाएगी।

77. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे (हर विधानसभा क्षेत्र में 2000 कैमरे) लगाने की घोषणा की थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1.32 लाख

सीसीटीवी कैमरा पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और अब हमारी सरकार ने आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशनों में लगाए जाने वाले कैमरों समेत इनकी संख्या 1.4 लाख से बढ़ाकर 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरे कर दी है। 1.40 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का द्वितीय चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 2020–21 में पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020–21 में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो संशोधित अनुमान 2019–20 में उपलब्ध कराए गये 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा।

78. हमारी सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी सभी स्ट्रीट लाइटों को बदलेगी और उनकी जगह बिजली की किफायत करने वाली एलईडी लाइटें लगाएगी। इससे स्ट्रीट लाइटों की संचालन लागत 6 करोड़ रुपये मासिक से घटकर 3 करोड़ रुपये मासिक रह जाएगी। इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये होगी और इसका कार्य 2020–21 में शुरू किया जाएगा।

79. हमारी सरकार आम जनता को वाई–फाई के निःशुल्क इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है। इसके लिए करीब 11,000 हॉट स्पॉट का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनमें से करीब 2000 वाई–फाई हॉट स्पॉट बनाए जा चुके हैं।

80. तीन नयी परियोजनाएं–स्लिप रोड ब्रिज का निर्माण (कोंडली पुल पर) और गाजीपुर ड्रेन के ऊपर अतिरिक्त पुल बनाकर हिंडन नहर से धर्मशिला तक सड़क को चौड़ा करने और नये अशोक नगर मेट्रो स्टेशन तक का कार्य वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू किया जाएगा। तीनों परियोजनाओं से लोगों के बहुमूल्य समय की बचत होगी और उनकी ऊर्जा और धन भी बचेगा। इन पुलों के बन जाने से प्रदूषणकारी उत्सर्जन के स्तर में भी कमी आएगी।

81. सड़कों पर यातायात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहरीकरण में आ रही तेजी और यातायात घनत्व बढ़ने से सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सड़कों की भौगोलिक स्थिति, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं और चौराहों के गोल चक्करों में सुधार की

आवश्यकता हैं। मैं इसके लिए 193 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नयी योजना ''सड़क अवसंरचना में सुधार'' का प्रस्ताव करता हूँ।

आवास और शहरी विकास

82. महोदय, हमारी सरकार अनधिकृत कालोनियों में रहने की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है और इनमें विकास का कार्य फास्ट ट्रैक मोड में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत उनमें बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे सड़कों और नालों, पानी की आपूर्ति, जलमल और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों के लिए धनराशि डीजेबी, डीएसआइआइडीसी और आइएंडएफसी जैसी कार्यपालक एजेंसियों को दी जाती है। अब तक दिल्ली की 1797 अनधिकृत कालोनियों में से 1281 में विकास कार्य पूरे हो गये हैं/चल रहे हैं। 2020–21 के अंत तक सभी कालोनियों में विकास कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं इन कालोनियों में बुनियादी ढाचे के विकास के लिए बजट अनुमान 2020–21 में 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं जबकि संशोधित बजट अनुमान 2019–20 में इसके लिए 1520 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे।

83. स्थानीय स्तर पर सामान्य विकास कार्यों के पूरक के रूप में और इसमें रही कमियों को दूर करने के लिए बजट अनुमान 2020–21 में 400 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नयी योजना ''मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास'' का प्रस्ताव किया गया है जो वर्तमान मुख्यमंत्री सड़क पुनरोत्थान योजना के 450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होंगे। दिल्ली के हर गली–कूचे में जनता की सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखने के लिए 2020–21 में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय से ''मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना'' नाम की नयी योजना का भी प्रस्ताव किया गया है।

84. डीयूएसआईबी और दिल्ली सरकार की जमीन पर बनी झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में डीयूएसआईबी द्वारा हाल में कराए गये मांग सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी जे.जे. बस्तियों में रहने वाले 65,000 परिवारों को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र दे दिये गये हैं। डीयूएसआईबी झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास का कार्य करता है और उन्हें रहने योग्य निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की तरह के फ्लैट उपलब्ध कराकर इज्जत से जिंदगी जीने का मौका देता है। ''जहां झुग्गी, वहां मकान'' योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्के मकान उपलब्ध कराकर बसाने का वादा किया है ताकि उनकी आजीविका संबंधी गतिविधियों में किसी तरह का व्यवधान न आए। हमारी सरकार ने इसी सिलसिले में 11 दिसम्बर 2017 को ''मुख्यमंत्री आवास योजना'' के बारे में अधिसूचना जारी की। इसके लिए पुनर्वास की पात्रता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 01 जनवरी 2015 की गयी। इससे झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने वाले 90 प्रतिशत लोग फ्लैट पाने के पात्र हो जाएंगे। डीयूएसआईबी अपनी और दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी 138 मौजूदा झुग्गी बस्तियों को पांच कि.मी. के दायरे में शौचालय, स्नानागार, रसोई से युक्त दो कमरों के फ्लैटों में स्थानांतरित करेगा। ये फ्लैट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तर्ज पर बनाए जाएंगे।

85. हमारी सरकार प्रत्येक झुग्गी बस्ती में साफ–सुथरा माहौल उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी। इन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाकर अंधेरे स्थानों को समाप्त करेगी। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियां मौजूदा स्ट्रीट लाइटों में बढ़ोतरी करेंगी और उनके रखरखाव में भी सुधार किया जाएगा।

86. मैं वर्ष 2020–21 के लिए आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए कुल 3723 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं पर अमल के खर्च का प्रस्ताव करता हूँ।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

87. महोदय, यमुना नदी नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और शाहदरा नाले जैसे अनेक नालों से प्रदूषित हो रही है। हमारी सरकार इन नालों को साफ करने और इनके सौंदर्यकरण के लिए प्रयास करेगी। यमुना को साफ–सुथरा करना भी 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के तहत मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की गारंटियों में शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान हम यह कार्य नजफगढ़ नाले से आरंभ करेंगे। इसके तहत, ढांसा बार्डर से बसई दारापुर पुल तक 45 किलोमीटर तक भूजल का स्तर बढ़ाने और सतह की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए गाद निकालने/नालों को गहरा करने, बांध/बैराज बनाने का काम किया जाएगा। नजफगढ़ नाले के किनारे की खाली जमीन पर पार्क और मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी उपाय अगले 3 वर्ष में पूरे कर लिए जाने की आशा है और इन पर 2,000 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। मैं 2020–21 में तटबंध योजना के अंतर्गत इस कार्य के लिए 410 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

88. महोदय, मैंने अपने पिछले बजट में दिल्ली में भूजल स्तर में सुधार और सतत जल उपलब्धता के लिए '1000 एकड़ क्षेत्र में बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए पल्ला यमुना बाढ़ क्षेत्र में जलाशय के निर्माण की योजना' घोषित की थी। इस संबंध में यमुना बाढ़ क्षेत्र में वजीराबाद बैराज की ऊपरी धारा के अतिरिक्त जल संचय के लिए 40 एकड़ क्षेत्र में जलाशय निर्माण की पायलट परियोजना अगस्त 2019 में शुरु की गई। इसका आंशिक कार्य 17.76 एकड़ क्षेत्र में पूरा हो चुका है। शेष कार्य वर्ष 2020 में पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020–21 के बजट में इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ।

ग्रामीण विकास व पषुपालन

89. महोदय, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन 2017 में दिल्ली के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने अपने गठन के बाद से 1,235 करोड़ रुपये

लागत की कुल 1,029 परियोजनाओ को मंजूरी दी है। इसमें से 505.65 करोड़ रुपये लागत के 458 निर्माण कार्यो के खर्च की स्वीकृति दे दी गयी है। 193 कार्य पूरे किये जा चुके हैं और 183 का काम चल रहा है और 2020–21 में इसके पूरा हो जाने की संभावना है। मैं 2020–21 के बजट में दिल्ली के गांवों में विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं जबकि संशोधित अनुमान 2019–20 में इसके लिए 301.99 करोड़ रुपये दिये गये थे।

90. महोदय, तीस हजारी में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य करने वाले एक पशु चिकित्सालय ने काम करना शुरू कर दिया है। पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गाजीपुर और पालम में दो और पशु चिकित्सालय सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक दो पारियों में चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूर–दराज इलाकों में पशुओं के इलाज के लिए दो मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिकों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अपने लगातार प्रयासों की श्रृंखला में हम सप्ताह में सातो दिन और चौबीसों घंटे विशिष्ट और आपात सेवाएं उपलब्ध कराने वाले 5 और पॉलीक्लीनिक शुरू करेंगे और एक राज्य स्तरीय नैदानिक प्रयोगशाला सुविधा केन्द्र बनाया जाएगा और 5 जिला स्तरीय नैदानिक प्रयोगशाला सुविधा केन्द्रों की स्थापना 2020–21 में की जाएगी।

व्यापार और उद्योग

91. महोदय, मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीति आयोग द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक की दृष्टि से दिल्ली शीर्ष स्थान पर है और इसे 100 अंक मिले हैं जबकि अखिल भारतीय औसत 65 का है।

92. दुनिया भर में दिल्ली की ख्याति स्टार्ट अप्स के केन्द्र के रूप में है। सरकार दिल्ली के लिए नई स्टार्ट अप्स नीति को अंतिम रूप देने में लगी है और एक नवसृजन/इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने जा रही है। सरकार ने एक महा आयोजन शुरू करने की भी योजना बनायी है जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्टार्ट अप्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि स्टार्ट अप्स वाले माहौल में सभी संबद्ध पक्ष नये–नये विचारों और टेक्नोलाजी के बारे में विचारों का आदान–प्रदान कर सकें। इसका मूल उद्देश्य स्टार्ट अप कंपनियों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। बजट अनुमान 2020–21 में स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने और स्टार्ट अप समारोह के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

93. दिल्ली इन्नोवेशन केन्द्र को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित दिल्ली एम्पोरियम भवन में 7476 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह स्टार्ट अप्स अत्याधुनिक सुविधाओं, जैसे कान्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा, वाई–फाई संपर्क, मेंटर की सहायता हासिल करने के लिए साथ काम करने की जगह और इसी तरह की तमाम अन्य सामान्य कारोबारी सेवायों से सुसज्जित होगा।

94. सरकार ने कारोबारी सुविधा से संबंधित कई सुधार किये हैं और कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान और स्वचालित बना दिया है। कारोबारी सहूलियत से संबंधित विभिन्न सुधार इसलिए किये गये हैं ताकि कारोबार शुरू करना, निर्माण परमिट हासिल करना, जीएसटी पंजीकरण, संपत्ति पंजीकरण, नया बिजली कनेक्शन हासिल करना, ऑनलाइन/स्टांप ड्यूटी की नकदी रहित भुगतान आदि में आसानी हो। आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और गोदाम की भवन–योजना की स्वीकृति अब एक साझा आवेदन पत्र भरकर और ई–पेमेंट गेटवे से 'सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली' के जरिए की जाने लगी है। मैं बजट अनुमान 2020–21 में कारोबारी सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

श्रम और रोजगार

95. महोदय, हमारी सरकार श्रम विभाग के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नियोजित कामगारों को विभिन्न श्रमिक कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करने के साथ–साथ उनके कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों को लागू कर रही है।

96. हमारी सरकार काम करने के माहौल में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि श्रमिक शोषण का शिकार हुए बिना इज्जत के साथ काम कर सकें : (1) दिल्ली में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को नियमित करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बिल–2019; (2) विभिन्न कल्याण योजनाओं का फायदा पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम–2019; (3) श्रम कानूनों के दायरे से बाहर पल्लेदार और इसी तरह के अन्य श्रमिकों के संरक्षण और लाभ के लिए दिल्ली मथाडी, पल्लेदार और अन्य असंरक्षित श्रमिक (रोजगार और कल्याण विनियमन) विधेयक–2019।

97. दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को इज्जत के साथ काम करने का मौका देने और उन्हें सुरक्षित तथा अच्छा कामकाजी माहौल उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने श्रमिक हैल्पलाइन (155214) शुरू की है। इसका संचालन पेशेवर तरीके से किया जाता है और सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध रहती है। श्रम विभाग ने ऐसी 33 सेवाओं की पहचान की है जो कारोबार करने की सुविधा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएंगी। इनमें से 20 सेवाएं पहले ही ऑनलाइन प्रदान की जाने लगी हैं और दिल्ली सरकार के ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर चालू हैं। बाकी सेवाएं भी जल्द इसमें शामिल कर ली जाएंगी।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

98. महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, मुसीबत में पड़ी महिलाओं और दिव्यांगजनों के सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक कल्याण हेतु प्रतिबद्व है, जिसके लिए 8.12 लाख लाभार्थियों को 2,000 रुपये से 2,500 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। 2020–21 के बजट में मैं इन लाभार्थियों के लिए 2,520 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ जबकि 2019–20 के बजट अनुमानों में इसके लिए 2,152 करोड़ रुपये रखे गये थे।

99. 2020–21 में 20 करोड़ रुपये की लागत से 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवहार परिवर्तन' नाम की एक नयी योजना का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

100. तत्काल आवश्यक चिकित्सकीय उपचार, सामान्य इलाज, स्ट्रोक या किसी अन्य बीमारी होने, स्थायी या आंशिक विकलांगता उत्पन्न करने वाली दुर्घटना के मामलों के लिए मैं 2020–21 में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नयी 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना' का प्रस्ताव करता हूँ।

101. मौजूदा 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना' का विस्तार किया गया है और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के साथ–साथ दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध 46 कोचिंग संस्थानों के जरिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना के तहत 47 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग दी गयी और 13 ने जेईई मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाइ किया जिनमें से तीन को आईआईटी, एनआईटी और एनएसयूटी में दाखिला मिला; 58 विद्यार्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग दी गयी और 22 ने एनईईट परीक्षा के लिए

क्वालीफाइ किया। मैं 2020–21 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं जबकि 2019–20 के संशोधित अनुमान में इस के लिए 17 करोड़ रुपये रखे गये थे।

102. मैं 2020–21 में 9वीं कक्षा से 12वीं तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना' नाम की एक नयी योजना का प्रस्ताव करता हूं। नवीं और दसवीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें इस योजना के तहत 5,000 रुपये वार्षिक का वजीफा दिया जाएगा। इसी तरह ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं उन्हें 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मैं इस योजना के लिए 2020–21 के बजट में 150 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

103. हमारी सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान के रूप में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की है। इसके अंतर्गत वे देश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने भविष्य में भी इस योजना को जारी रखने और अगले पांच वर्षों में 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा देने का आश्वासन दिया है। मैं वर्ष 2020–21 के बजट में 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान करता हूं। मैं दिल्ली दर्शन योजना के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कर रहा हूं जिसमें दिल्ली भ्रमण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

104. 'मुख्यमंत्री एडवोकेट वैलफेयर फंड योजना' के तहत दिल्ली के निवासी और वकालत करने वाले पंजीकृत वकीलों को मेडीक्लेम पॉलिसी, ग्रुप इनश्योरेंश पॉलिसी, ई–लाइब्रेरी और क्रैच सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसके लिए अगले वित वर्ष में भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

105. अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत (बजट शीर्ष 789 के तहत) वर्ष 2020–21 में 1,534 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है जबकि वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमान में इसके लिए 1,403 करोड़ रुपये रखे गये थे।

106. मैं सामाजिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए 2020–21 में कुल 4,466 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रस्ताव करता हूं। समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3,868 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 3,696 करोड़ रुपये राजस्व परिव्यय के और 172 करोड़ रुपये पूंजी परिव्यय के शामिल हैं।

पर्यटन

107. महोदय, दिल्ली के अंदर देश की टूरिज्म कैपिटल बनने की संभावनायें एवं संसाधन उपलब्ध हैं। हैरिटेज मोनूमेंट से लेकर आधुनिक बाजारों तक, पुरानी दिल्ली की पारंपरिक–सुबहों से लेकर नाईट–लाईफ तक देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन ब्रांडिग और जानकारी के अभाव में अधिकतर टूरिस्टस दिल्ली को एक ट्रांजीशन प्वाईंट के रूप में ही लेकर चलते हैं इसकी वजह से दिल्ली में आने वाला टूरिस्ट औसतन एक दिन दिल्ली में बिताता है। जबकि लंदन, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहरों में एक टूरिस्ट औसतन 3 दिन बिताता है। दिल्ली सरकार योजना बना रही है कि दिल्ली आने वाला टूरिस्ट औसतन कम से कम दो दिन दिल्ली में जरूर बिताये। केवल एक दिन के फर्क से ही दिल्ली में लाखों नये रोजगार और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के नये अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत दिल्ली के टूरिज्म की री–ब्रांडिग की जायेगी और देशी व विदेशी पर्यटकों तक देश–विदेश में दिल्ली को एक टूरिज्म ब्रांड के रूप में पेश किया जायेगा। दिल्ली आने वाले हरेक देशी–विदेशी पर्यटक, वो चाहे रेलवे स्टेशन पर आये

या हवाई अड्डे पर, उन्हे दिल्ली को जानने और दिल्ली घूमने के लिए प्रेरित किया जायेगा। मैं वर्ष 2020–21 के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नयी योजना 'ब्रांडिंग दिल्ली' का प्रस्ताव करता हूं।

108. दिल्ली के डायनेमिक स्वरूप को दिल्ली के टूरिज्म का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछले वर्ष बिना पटाखे जलाये, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की पहल की और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ लेजर शो का आयोजन किया। इसकी व्यापक सराहना हुई और दिल्ली के लोगों को बड़ा अच्छा संदेश गया। 'दिल्ली की दिवाली' का आयोजन अगले साल भी होगा। इसी के साथ अगले वर्ष पूर्वांचल उत्सव के नाम से भी एक नया उत्सव दिल्ली में शुरू करने का प्रस्ताव है। हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यह जरूरत महसूस की गयी है कि लोगों में सांप्रदायिक सदभाव बनाये रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किये जायें इसके लिए 'कैम्पेन फार कम्यूनल हारमनी' (साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान) की नयी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

109. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बजट भाषण का भाग–ख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

भाग–ख

110. माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई 2017 में (जीएसटी) पर अमल के बाद यह सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। जीएसटी के लागू होने से हमारे उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने योग्य हो गये हैं। जनवरी 2020 तक कुल 4.30 लाख नये जीएसटी पंजीकरण किये गये। इनमें से 2.02 लाख दिल्ली राज्य के अधिकार क्षेत्र में थे। दिल्ली में फरवरी 2020 तक केन्द्रीय और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या (नये और स्थानांतरित) 7.79 लाख हैं।

111. ई–वे बिल माल ले जाने में काम आने वाला इलेक्ट्रानिक वे–बिल यानी बिल्टी है जिसे ई–वे बिल पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2019 में जनवरी से दिसंबर तक कुल 2.94 करोड़ ई–वे बिल निकाले गये जिनमें से राज्य के भीतर माल भेजने के लिए निकाले गये ई–वे बिलों की संख्या 98.76 लाख रही।

112. नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप करीब 89 प्रतिशत कर–दाताओं ने जनवरी 2020 तक जीएसटीआर–3बी फाइल किये और 67 प्रतिशत ने जीएसटीआर–1 फार्म समय पर फाइल किये। समय पर रिटर्न भरने की स्थिति में और सुधार लाने के लिए विभाग और प्रयास करेगा।

113. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित नयी पहल इस प्रकार हैं: (1) पंजीकरणों को आधार से जोड़ना; (2) इनवाइस का मिलान करना; (3) आरएफडी को ई–वे बिल के साथ समन्वित करना; (4) विवरणियों का नया प्रारूप।

114. वर्ष 2019–20 के लिए (फरवरी 2020 तक) वैट समेत शुद्ध जीएसटी राजस्व 22,808 करोड़ रुपये है और फरवरी 2020 तक 7,436 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त हुए। इससे 17.21 प्रतिशत की विकास दर का पता चलता है जिसमें वैट संकलन समेत जीएसटी शामिल है।

115. दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानो में वैट समेत जी.एस.टी. का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये का है जो 2019–20 में 27,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित संशोधित अनुमान से 11.11 प्रतिशत अधिक है।

116. शराब की तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने के लिए हमारी सरकार नियमित रूप से खुफिया सूचना एकत्र कर रही है। लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे हर बोतल की शत–प्रतिशत जांच के बाद ही शराब की बिक्री करें ताकि राजस्व के नुकसान की कोई आशंका न रहे और विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेची गयी शराब की हर बोतल के स्रोत का

ESCIMS से पता लगा सके। आबकारी विभाग ने 2019–20 में (फरवरी 2020 तक) शराब का अवैध धंधा करने वालों और अवैध शराब सप्लाई करने वालों के खिलाफ 873 मामले दर्ज किये हैं जबकि 2018–19 में इस तरह के 806 मामले दर्ज किये गये थे। विभाग ने 2019–20 में (फरवरी 2020 तक) 456 वाहन भी जब्त किये जबकि 2018–19 में 395 वाहन जब्त किये गये थे। वर्ष 2019 में 653 वाहनों की ई–नीलामी (जिसमें 343 वाहन बिके) एमएसटीसी लि. के माध्यम से की गयी।

117. खुले में शराब पीने की शिकायतें बार–बार मिलने और शराबियों द्वारा पैदा की गयी अफरा–तफरी को देखते हुए दिसंबर 2019 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने को रोकना था। 2019 के दौरान (फरवरी, 2020 तक) करीब 1,311 लोगों को पकड़ा गया जबकि 2018–19 में 609 को पकड़ा गया था।

118. वर्ष 2019–20 के दौरान आबकारी से प्राप्त कुल राजस्व (फरवरी, 2020 तक) 4,669 करोड़ रुपये हैं और विकास दर 3.73 प्रतिशत है। 2020–21 के लिए आबकारी राजस्व का प्रस्तावित लक्ष्य 6,300 करोड़ रुपये है जो 2019–20 के संशोधित अनुमान में 14.55 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

119. महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन के विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

....